

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 25, बुधवार, शाके 1943-मार्च 16, 2022 <i>Phalguna 25, Wednesday, Saka 1943- March 16, 2022</i>	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2022

संख्या एफ. 13(11)विशा/विस/2022 :-राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 जैसा कि दिनांक 16 मार्च, 2022 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

Bill No. 11 of 2022

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2022

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- In sub-section (8) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No.15 of 1956),-

(i) for the existing expression “where before 17th June, 1999”, the expression “where before 31st December, 2021” shall be substituted; and

(ii) in proviso, the existing clauses (i) and (ii) shall be renumbered as (ii) and (iii) respectively and before the clause (ii) so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:-

“(i) nothing in this sub-section shall apply to any land in respect of which any allotment has been made or Patta given by a Housing Co-operative Society after 16th June, 1999;”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government is of the view that there are certain difficulties in conversion of agricultural lands which have been used for non-agricultural purposes under sub-section (8) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. The said sub-section applies on agricultural land held and used for non-agricultural purposes before 17th June, 1999.

In last two decades, socio-economic growth and various other reasons have led to rapid urbanization in urban areas of the State. Various kinds of non-agricultural developments have taken place on agriculture lands. Due to this cut-off date of 17th June, 1999 problems are being faced in conversions of such non-agricultural developments in urban areas.

In the larger interest of public already inhabiting and carrying on their livelihood on such lands which have been used for non-agricultural purposes after 17th June, 1999, the State Government is of the opinion that in order to facilitate conversion of these lands and to provide such people with basic rights of minimum infrastructure facilities, the cut-off date of 17th June, 1999 should be extended to 31st December, 2021. The State Government is also of the view that any land in respect of which any allotment or Patta has been given by a Housing Co-operative Society after 16th June, 1999 should be excluded from the scope of sub-section (8) of section 90-A. Accordingly, sub-section (8) of section 90-A is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

2022 का विधेयक सं.11**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)****राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022****(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क की उप-धारा (8) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "17 जून, 1999 के पूर्व" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर, 2021 के पूर्व" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) परन्तुक में, विद्यमान खण्ड (i) और (ii) को क्रमशः (ii) और (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (ii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(i) इस उप-धारा की कोई भी बात ऐसी किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी, जिसके संबंध में किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा 16 जून, 1999 के पश्चात् कोई आबंटन किया गया है या पट्टा दिया गया है;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार का यह विचार है कि ऐसी कृषि भूमियाँ, जिनका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया है, के संपरिवर्तन में कतिपय कठिनाइयाँ हैं। उक्त उप-धारा 17 जून, 1999 से पूर्व गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोग में ली गयी कृषि भूमि पर लागू होती है।

विगत दो दशकों में, सामाजिक-आर्थिक विकास से और विभिन्न अन्य कारणों से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में तीव्र नगरीकरण हुआ है। कृषि भूमियों पर विभिन्न प्रकार के गैर-कृषिक विकास हुए हैं। 17 जून, 1999 की इस अंतिम तारीख के कारण नगरीय क्षेत्रों में ऐसे गैर-कृषिक विकासों के संपरिवर्तन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी भूमियों, जो कि 17 जून, 1999 के पश्चात् गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली गयी हैं, पर पहले से ही निवास कर रही और अपनी जीविका चला रही जनता के वृहत् हित में, राज्य सरकार का यह मत है कि इन भूमियों के संपरिवर्तन को सुकर बनाने के लिए और ऐसे व्यक्तियों को न्यूनतम अवसंरचना सुविधाओं के आधारभूत अधिकार उपलब्ध करवाने के लिए, 17 जून, 1999 की अंतिम तारीख को 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार का यह भी मत है कि ऐसी किसी भूमि, जिसके संबंध में किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा 16 जून, 1999 के पश्चात् कोई आबंटन किया या पट्टा दिया गया है, को धारा 90-क की उप-धारा (8) की परिधि से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 90-क की उप-धारा (8) यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

Government Central Press, Jaipur.